



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1  
PART 1—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1/  
No. 1

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1984/पौष 17, 1905  
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/PAUSA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
संकल्प

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

वाइस एडमिरल एम० के० गय, फ्लैग ऑफिसर,  
सर, कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमाण्ड  
श्री एस० एस० शुक्ला, वित्तीय सलाहकार  
नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
श्री दिनेश कुमार जन, संयुक्त सचिव (पत्तन)  
नौवहन और परिवहन मंत्रालय

सदस्य सचिव श्री एच० एन० फोनेहार, प्रबंध निदेशक  
इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन

सं० पी० डब्ल्यू०/पी० ई० ओ०-47/82 :—प्राक्कलन समिति सातवों लोकसभा (हमकी 12वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिश सं०-92) ने यह सिफारिश की है कि मंडलान्तों के प्रशासन को अधिक कुशल और परिणामपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया का व्यापक समीक्षा करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार समिति नियुक्ति की जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश के अनुपालन में मंडलान्त सुधार समिति गठित करने का निश्चय किया है। इस समिति का संरचना निम्न प्रकार होगी—

अध्यक्ष श्री डा० ए० ए० ए०  
सदस्य श्री ए० ए० ए० ए० ए० ए०  
श्री एस० ए० ए० ए०  
श्री हिमेश चंद्र  
श्री ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०  
श्री के० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०  
श्री ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०  
श्री ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०  
श्री आर० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०  
(निक सुधार) गृह मंत्रालय

2. समिति का कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार होगा—

(i) देश के मंडलान्तों के प्रशासन से सम्बंधित मौजूदा कानूनी ढांचा, सरकार द्वारा मंडलान्तों को जारी किए गए अनुदेश/मार्गदर्शिका, उनकी प्रशासनिक और प्रचालन (वागों में शामिल नहीं) प्रवृत्ति, संसाधन/सामग्री का प्रयोग, नियंत्रण प्रबंध और कार्य निष्पादन आंच करना; और

(ii) (a) उनकी कार्यप्रणाली और संरचना (वर्कफ्लो और कार्यकरण का प्रारंभ) के लिए, प्रेरित कानूनी, संगठनात्मक और प्रशासनिक पुनर्गठन,

(ख) पत्तन क्षेत्र से जुड़ाई गई अतिरिक्त धनराशि का निवेश करने के लिए अपनाए जाने वाले विनियमों की विधि और नीति,

(ग) संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि में जनशक्ति, उपकरण आदि का एक पत्तन से दूसरे पत्तन में हस्तांतरण,

(घ) कार्गो हैंडलिंग उपकरण और अन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण,

(ङ) पत्तन प्रचालक और पत्तन की लागत और मूल्य निर्धारण को युक्तिमंगत बनाना,

(ज) पत्तन प्रबंध में व्यावसायिकता के प्रवर्तन और तकनीक में विशिष्टता का प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित संस्थागत व्यवस्था और निवेश,

(झ) पत्तन क्षेत्र के विकास की कुल परिवहन पद्धति, और इसकी आधारभूत सुविधा वी अन्य अनुपंगी पद्धति.

3. समिति यदि यह आवश्यक समझे तो आमतौर पर यह देश के आर्थिक विकास तथा खासकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी लाने के लिए महापत्तनों की उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए अन्य सुझाव भी देगी।

4. समिति किसी ऐसे विशेष या व्यक्ति जिसके पास इस क्षेत्र में विशेष जानकारी है, उसे सहयोजित कर सकती है। आवश्यकतानुसार यह उपरोक्त क्षेत्र में से किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए उप-दल गठित कर सकती है।

5. समिति की सहायतार्थ लिपिकवर्गीय कर्मचारी होंगे जिनकी नियुक्ति अलग से की जाएगी।

6. समिति अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर पेश करेगी।

7. समिति अपनी अलग कार्य-पद्धति तैयार करेगी। यदि यह आवश्यक समझे तो कोई भी सूचना मांग सकती है और साक्ष्य ले सकती है। भारत सरकार के सभी महापत्तनों और मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारें इस समिति को आवश्यकतानुसार सूचना और सहायता प्रदान करेंगी।

8. अग्रासकीय सदस्यों की यात्रा में संबंधित यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते का भुगतान भारत सरकार गौरवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। शासकीय सदस्यों में संबंधित खर्च उस संगठन द्वारा वहम किया जाएगा जिसमें वे कार्यरत हैं।

दिनेश कुमार शैल, सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT RESOLUTION

New Delhi, the 7th January, 1984

No. PW/PEO-47/82.-In pursuance of a recommendation made by Estimates Committee—Seventh Lok Sabha (Recommendation No. 92 contained in its 32nd Report) that administrative reforms committee be appointed to take up a comprehensive review of the administrative systems and procedure obtaining at major ports with the object of making their

administration more efficient and result-oriented, Government of India have decided to set up a Major Ports Reforms Committee consisting of the following :

Chairman	Shri D.D. Sathé
Members	Shri R. Balasubramanian Shri M.R. Shroff Shri Hiten Bhaya Shri B.K. Rao, Director General, (Shipping) Shri K.K. Uppal, Chairman, Bombay Port Trust. Shri T.C. Dutt, Chairman, Calcutta Port Trust. Shri R. Parameswar, Additional Secretary (Administrative Reforms), Ministry of Home Affairs. Vice Admiral M.K. Roy, Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command. Shri S.S. Shukla, Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport Shri D.K. Jain, Joint Secretary (Ports), Ministry of Shipping and Transport.
Member Secretary	Shri H.N. Fotedar, Managing Director, Indian Ports Association.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine the existing legal framework governing the administration of major ports in the country, instructions/guidelines issued by the Government to the major ports, their administrative and operational (including cargo handling) systems, labour productivity and motivation, financial management and performance; and

(ii) To make suitable recommendations regarding :

(a) the statutory, organisational and administrative restructuring required for securing integrated and coordinated development and functioning of the ports;

(b) the funding pattern and the policy to be followed for investment of any surpluses generated in the port sector;

(c) the inter-port transfer of manpower, equipment etc., with a view to ensuring optimal utilisation of resources;

(d) the modernisation of cargo handling equipment and other services;

(e) the rationalisation of port operations and port costing and pricing;

(f) the institutional arrangements and inputs required for promoting professionalism and encouraging specialisation of techniques in ports' management;

(g) the development of the port sector pari passu with the other sub-systems of the total transportation system and its infrastructure.

3. The Committee may make such other recommendations as it considers necessary to enable the major ports to fulfil their role as a catalyst for the country's economic development in general and international trade in particular.

4. The Committee may co-opt any expert or person having specialised knowledge of any subject connected with its deliberations. It may set up, if necessary, sub-groups for making a study in any of the aforesaid areas.

5. The Committee will be assisted by supporting secretarial staff to be appointed separately.

6. The Committee will submit its report within a period of one year.

7. The Committee will devise its own procedure. It may call for such information and take such evidence as it may con-

sider necessary. All Major Port Trusts and the Ministries/ Departments of the Government of India and State Governments will furnish such information and render such assistance as may be required by the Committee.

8. The expenditure on account of TA/DA etc. in connection with the journeys of the non-official members will be borne by the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport. The expenditure on this account in respect of official members will be borne by the respective organisations in which they are working.

D.K. JAIN, Jt. Secy.

